

यूजीसी की पहल

मानव संसाधन विकास मंत्रालय करेगा फैसला

ऑनलाइन डिग्री देने के लिए मांगे सुझाव

डेली न्यूज अजमेर > 21 जुलाई

विद्यार्थियों का ऑनलाइन डिग्री हासिल करने का सपना जल्द पूरा होगा। यूजीसी ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों के नियमित अथवा दूरस्थ प्रणाली से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन डिग्री मुहैया कराने की योजना बनाई है। इसके लिए शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम लोगों से 18 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं। मौजूदा वक्त विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, कला, वाणिज्य, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विधि और अन्य संकाय में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हैं।



प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र-छात्राओं के लिए साल में एक बार परीक्षा देकर पास होने का ही विकल्प है। कुछेक निजी अथवा सरकारी विश्वविद्यालय को छोड़कर ऑनलाइन कोर्स में पढ़ने, और परीक्षा देकर त्वरित डिग्री का प्रावधान नहीं है।

20 % कोर्स हों ऑनलाइन

यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को सभी संकाय में 20 प्रतिशत कोर्स ऑनलाइन बनाने को कहा है। संस्थाओं को इसे यूजीसी के स्वयं प्लेटफॉर्म से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद विभिन्न चरणों में पाठ्यक्रमों को 40, 60, 80 और शत-प्रतिशत ऑनलाइन किया जाएगा।

सरकार ने बनाई योजना

विद्यार्थियों को ऑनलाइन डिग्री उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी ने योजना बनाई है। सचिव प्रो. जसपाल सिंह संधु ने बताया कि इसमें विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज में नियमित अथवा दूरस्थ

शिक्षा प्रणाली से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों का नियमित अथवा दूरस्थ शिक्षा के तहत कक्षाओं में पढ़ना जरूरी होगा। विद्यार्थी एक या अधिक कोर्स का चयन कर पढ़ाई कर सकेंगे।

मांगे व्यापक स्तर पर सुझाव

यूजीसी ने शिक्षकों, विद्यार्थियों और आमजन से ऑनलाइन कोर्स और डिग्री उपलब्ध कराने को लेकर सुझाव मांगे हैं। यह सुझाव 18 अगस्त तक यूजीसी को भेजे जा सकेंगे। यूजीसी सीमित दायरे में ही ऑनलाइन डिग्री मुहैया कराएगी। किसी संस्था को पूर्ण स्वायत्तता अथवा अपने स्तर पर ऑनलाइन

यह होगा फायदा

- ▶ विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ने और परीक्षा देने का अवसर
- ▶ त्वरित डिग्री/डिप्लोमा होगा उपलब्ध
- ▶ वैश्विक स्तर तक बढ़ेगा शिक्षा का दायरा
- ▶ विश्वविद्यालयों की लेटलतीफ डिग्री देने की प्रवृत्ति पर अंकुश

डिग्री/डिप्लोमा जारी करने की अनुमति नहीं मिलेगी। लोगों के सुझाव को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा।